मूल्य एक प्रति 3.00 रु.
Registered with the Registrar of News Paper (Govt. of India) Vide R.N.I. No. 39299/81 On The Way Half Century 50 Monday & Tuesday every week on Delhi Postal Regd. No. DL(E)-20/5174/2021-23

व्यापार एक्सप्रेस
(हिन्दी साप्ताहिक)

Office : 2718, Street No. 5, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-110032
Mob.: +91-9312625326, 9717513928
Email: vyaparexpress50@gmail.com, vyaparexpress@ymail.com
CHIEF EDITOR : T.R. ARORA
www.vyaparexpress.co

वर्ष 42 अंक 07 • 14 फरवरी 2022 – 20 फरवरी 2022 प्रकाशन की तिथि हर सोमवार वार्षिक मूल्य सप्लीमेंट्री सहित 1100/– पृष्ठ–4

बासमती धान के मल्यों में फिर आई तेजी

धान के भाव में तेजी से किसानों के चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई हैं और बासमती व 1121 धान का भाव 3900 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। सूत्रों के अनुसार, दूसरे देशों में धान की मांग बढ़ी है, जिसके चलते भाव में तेजी दर्ज की जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में सीजन की शुरूआत में बासमती व 1121 धान 3300–3400 रुपए प्रति क्विंटल बिकना शुरू हुआ था और उसके बाद नवंबर आते–आते भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार चला गया था। कुछ किसानों ने भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल होने की आस में अपनी फसल को स्टॉक भी कर लिया था लेकिन नवंबर खत्म होते–होते भाव एकदम से डूबकी लगाने लगा और 3400 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। काफी जगहों पर किसानों ने खुलें में धान स्टॉक कर उपर तिरपाल से ढक दिया था लेकिन बार–बार हो रही बारिश के चलते धान खराब होने का डर सताने लगा था, इसी डर के चलते कुछ किसानों को कम भाव पर धान की फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जिन किसानों ने रिस्क उठाते हुए अब तक धान को स्टॉक रखा हुआ था, उन्हें अब फायदा मिलेगा।

इस सीजन में पहली बार बासमती धान का भाव 1121 धान से नीचे दर्ज किया गया है। इसके चलते बासमती धान बोने वाले किसानों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। हर साल बासमती धान का रेट 1121 धान से एक हजार से लेकर 1500 रुपए तक अधिक रहता था। इस सीजन की शुरूआत में भी बासमती धान 4500 रुपए प्रति क्विंटल बिका था लेकिन भाव में गिरावट आने पर 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं बासमती 408 किस्म का भाव भी गिरकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया।

पिछले सीजन में बासमती 408 धान 4000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा बिका था। फिलहाल बासमती धान का भाव 3500 से 3600 और बासमती 408 धान का भाव 3200 से 3250 प्रति क्विंटल बना हुआ है।

चावल के वैश्विक उत्पादन और भारत के निर्यात में होगी बढ़ोत्तरी

वर्ष 2021–22 में चावल के वैश्विक उत्पादन में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिपींस में चावल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। हालांकि, भारत में चावल की खपत घटेगी लेकिन इसकी भरपाई नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की मांग बढ़ने से हो जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिपींस में चावल का स्टॉक बढ़ने से ब्राजील में कमी की आंशिक पूर्ति होगी।

भारत और पाकिस्तान का चावल निर्यात बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने अमरीकी चावल का भाव पांच डॉलर बढ़कर 610 डॉलर प्रति टन और उरुग्वे का चावल 545 डॉलर प्रति टन रहा। थाईलैंड का चावल 32 डॉलर उछलकर 429 डॉलर, जबकि वियतनाम का चावल आठ डॉलर गिरकर 392 डॉलर प्रति टन ऑफर हो रहा था। पाकिस्तानी चावल छह डॉलर गिरकर 359 डॉलर प्रति टन पर ऑफर हो रहा था जबकि भारतीय चावल पांच डॉलर बढ़कर 355 डॉलर प्रति टन रहा। अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने समूचे विश्व–में वर्ष 2020–21 में 50.74 करोड़ टन चावल पैदा होने की बात कही जो वर्ष 2021–22 में 51. 03 करोड़ टन (पिछले महीने 50.98 करोड़ टन) पहुंच सकता है। वर्ष 2019–20 में यह उत्पा5दन 49.88 करोड़ टन था।

वर्ष 2021–22 में भारत में चावल का उत्पादन 12.50 करोड़ टन होने का अनुमान है जो वर्ष 2020–21 में 12.22 करोड़ टन रहा। भारत में चावल उत्पादन वर्ष 2019–20 में 11.88 करोड़ टन था। भारत से वर्ष 2020–21 में चावल निर्यात 2.12 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2021–22 में 2 करोड़ टन रह सकता है। यह अनुमान पिछले महीने 1.87 करोड़ टन था। यह निर्यात वर्ष 2019–20 में 1.45 करोड़ टन था। यूएसडीए ने बांग्लोदेश में वर्ष 2020–21 में चावल उत्दान 3.46 करोड़ टन और वर्ष 2021–22 में 3.58 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है। ब्राजील में चावल का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 80. 01 लाख टन एवं वर्ष 2021–22 में 76.84 लाख टन रहने का अनुमान है। अमरीका में वर्ष 2020–21 में 72.24 लाख टन, चीन में 14.83 करोड़ टन, म्यांमार (बर्मा) में 1.26 करोड़ टन, फिलीपिंस में 1.24 करोड़ टन, इंडोनेशिया में 3.53 करोड़ टन चावल का उत्पामदन हुआ। जबकि, अमरीका में वर्ष 2021–22 में 60.90 लाख टन, चीन में 14. 89 करोड़ टन, म्यांमार (बर्मा) में 1.26 करोड़ टन, फिलीपिंस में 1.24 करोड़ टन, इंडोनेशिया में 3.54 करोड़ टन चावल का उत्पादन होने का अनुमान है। चावल की कुल वैश्विक खपत वर्ष 2020–21 में 50.27 करोड़ टन रही जबकि वर्ष 2021–22 में यह 51.03 करोड़ टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2020–21 में चावल का वैश्विक अंतिम स्टॉक 18.64 करोड़ टन रहा। वर्ष 2021–22 में यह 18.63 करोड़ टन रहने की संभावना है। यह वर्ष 2019–20 में 18.17 करोड़ टन रहा।

भारत से चावल का आयात करेगा श्रीलंका

श्रीलंका ने भारत और म्यांमार से 400,000 मीट्रिक टन चावल का आयात करने का फैसला लिया है। स्थानीय बाजार में चावल की कीमत स्थिर करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, भारत से 300,000 मीट्रिक टन और म्यांमार से 100,000 मीट्रिक टन चावल आयात करने में व्यापार मंत्रालय जुटा है। मई तक चावल का आयात किया जाएगा। मंत्रालय ने यह फैसला उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए लिया है। कुछ बड़े चावल मिलों की कर्टेल रणनीति के कारण उपभोक्ताओं को बाजार में ऊंची कीमत पर चावल खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। 20,000 मीट्रिक टन के हिस्सों में चावल की आपूर्ति की जाएगी। बाजार में इसे नियमित आधार पर जारी किया जाएगा।

देश अभी गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका में एक व्यक्ति हर साल 104.5 किलो चावल का उपभोग करता है। ऐसे में अनुमानित राष्ट्रीय चावल मांग 21 लाख टन है।

लालमिर्च के उत्पादन में कमी आने की आशंका

आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के तीनों प्रमुख उत्पादक राज्यों में चालू सीजन के दौरान लालमिर्च के उत्पादन में कमी आने की आशंका व्यक्त की जाने लगी है। इतना ही नहीं, किसानों की बिकवाली घटने से गुंटूर में लालमिर्च की आवक भी घट गई है। अतः आगामी दिनों में हाजिर में लालमिर्च मजबूत ही बनी रहने के आसार हैं। फसल के विकास के समय मौसम प्रतिकूल होने के कारण आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के तेलंगाना और कर्नाटक जैसे तीनों प्रमुख उत्पादक राज्यों में इस वर्ष लालमिर्च का उत्पादन घटने की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं।

इन आशंकाओं के मुताबिक, दक्षिण भारत में इस बार लालमिर्च के उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। इससे भी बुरी बात यह है कि भविष्य में आकर्षक कीमत मिलने की उम्मीद में किसानों ने भी अपनी लालमिर्च फसल की बिक्री घटा दी है। इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय गुंटूर में लालमिर्च की करीब 50 हजार बोरियों की आवक हुई होने की जानकारी मिली। आवक तुलनात्मक रूप से नीची होने और उठाव सुस्त मजबूत बना होने की रिपोर्ट मिली थी।

बेमौसम बारिश के कारण मसालों की कीमतों में जोरदार तेजी

- बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में भारी कमी
- फसलों को भारी नुकसान, बढ़े मसालों के दाम
- फसल कटने को थी, बारिश से कटी हुई मिर्च नुकसान
- लाल मिर्च का भीतरी भाग हुआ काला, फसल को फैका

भारतीय खाद्य संस्कृति में गरम मसालों का विशेष महत्व है, भारत में प्राचीन काल से ही मसालों का प्रयोग किया जाता रहा है कई लोग मसालों को बिक्री के बजाय कच्चे मसाले घर लाते हैं और उन्हें सुखाकर और फिर अपने तरीके से पीसकर स्टोर करते हैं आमतौर पर गर्मियां आते ही मसाले बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों हुई बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में भारी कमी देखी जा रही हैं वही अब सभी मसालों के दाम बढ़ गए हैं। मुंबई के एक मसाला व्यापारी के मुताबिक, पिछले साल नवंबर–दिसंबर में तैयार फसल के दौरान हुई बेमौसम बारिश ने मिर्च और अन्य मसाला फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। नतीजतन, इस साल खराब फसल के कारण मसालों के दाम 25 से 30 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

बेमौसम बारिश का कहर

पिछले साल नवंबर और दिसंबर में महाराष्ट्र में कई जगहों पर बेमौसम बारिश हुई थी जैसे ही किसान मसाला फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, तभी बेमौसम बारिश के कारण फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। ज्यादा बारिश से कटी हुई मिर्च को नुकसान पहुंचा था लाल मिर्च का भीतरी भाग पानी से काला हो गया था। जिसके बाद किसानों के पास खराब फसल को फेंकने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नही था। इसी तरह अन्य मसलों के साथ हुआ। नतीजतन, मसालों की आपूर्ति कम हो गई है और बाजार में अन्य मसालों की कमी के कारण मसालों की कीमत बढ़ गई है।

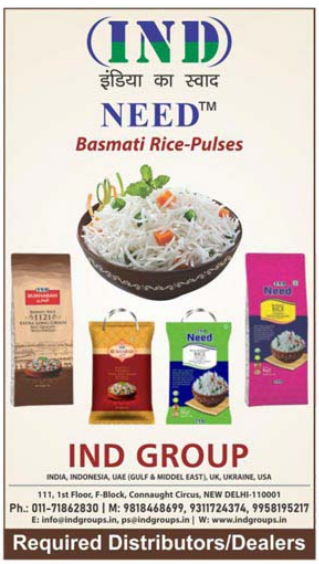

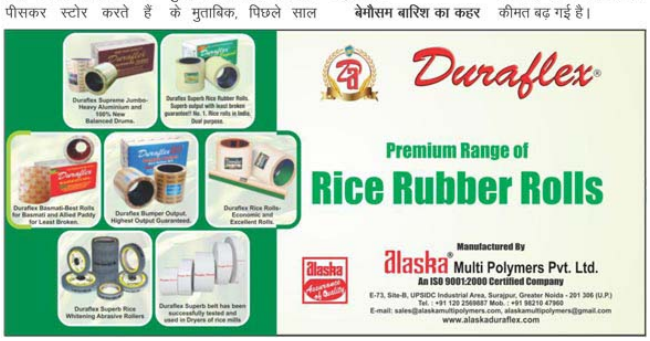

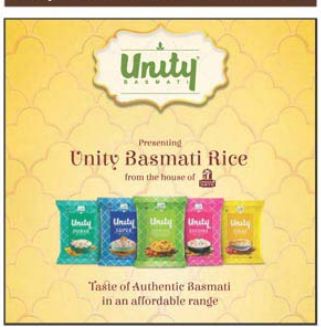

क्षेत्रीय मंडियों के बाजार भाव

कानपुरः गेहूं लूज 2150/2155, जौ 1975/2000, चावल मसूरी 2450/2550, चावल मोटा 2250/2400, देशी चना 5300/5325, चना छना 5850/5950, दाल चना 5900/6000, पिचकी 4800/5000, मटर दाल 7200/7400, अरहर लेमन 6600/6625, दाल अरहर 8900/9300, स्पेशल 8100/8400, उड़द एसक्यू 7250/7260, एफएक्यू 6600/6650, राजमा चित्रा 9900/13100, मूंग 5700/6500, मसूर छोटी 7600/7750, छांटी 8800/9300, सरसों 7300/7350, तिल सफेद 10000/10100 सोया (टीन) 2200/2250, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2550/2600, सरसो खल 3300/3350, पामोलिन 2150/2200, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1850/1950, मधुसूदन देशी घी 6200 वासुदेव 5950, परम प्रीमियम 6250 अलसी 9500/9700, धानियाः लोकल 9700/9800, राजस्थान 102000/10400

लखनऊः गेहूं दड़ा 2130/2140, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 4000/4050, स्टीम 5050/5150, लालमती 4400/3500, चावल (सोना) 4200/4300, दाल अरहर सवा नं. 7800/7900, पटका 8700/9300 रिजैक्शन 6700/7000, चना दाल 5950/6100, चना देशी छना 5950/6100, चना चापा छना 5900/6000, मटर विदेशी 7400/7500, उड़द साबुत (काला) 7200/8000, दाल उड़द (काली) 7900/8900, उड़द धोया 8000/8800, मसूर छोटी 7500/7700, मलका 8500/8800, किरानाः जीरा 18400/19800 लालमिर्च गुंटूर 17500/2300, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 5600/5700, धनिया एमपी 10100/12200, छोटी इलायची (किलो) 1000/1500, बडी इलायची 710/740, कालीमिर्च (किलो) 520/580, सुपारी (किलो) 580/630, सौंफ मोटी 9400/11800, मंगरैल 22500/23500, चिरौंजी (किलो) 1125/1250, मखाना 475/700

मुजफ्फरनगरः चाकू (कोल्ड) 1140/1270, खतौली 3540, देवबंद 3400, थाना भवन 3410, बुढ़ाना 3420, शामली 3390, चीनी हाजिर 3750/3850

हापुड़ः अनाज–दाल गेहूं 2215/2220, चावल परमल 2400/2450, डुप्लीकेट बासमती सेला 6100/6200, बासमती 1121 स्टीम 7400/7500, चना 5200/5250, चनादाल 5800/5900, काबली चना 7000/8500, राजमा देशी चित्रा 11500/13000, दाल अरहर 8000/8800, मसूर 7800/8000, उड़द देसी 6500/6700, दाल उड़द 7500/8500, मूंग यूपी 6500/6800, मूंग दाल 8000/9000, गुड़–चीनीः चीनी हाजिर 3800/3900

देश में जनवरी में सरसों की क्रशिंग रही 4.25 लाख टन

देश में सरसों की क्रशिंग जनवरी में 4.25 लाख टन रही। देश में 31 जनवरी तक सरसों की कुल क्रशिंग 84 लाख टन हुई जबकि आवक 79.95 लाख टन रही। देश में 31 जनवरी 2022 को किसानों के पास सरसों का कुल स्टॉक 1.05 लाख टन होने का अनुमान है। जबकि, प्रोसेसर्स और स्टॉकिस्टों के पास 95 हजार टन सरसों का स्टॉक है। सूत्रों के अनुसार, जनवरी में सरसों की आवक 3.65 लाख टन रही जो दिसंबर में 4.05 लाख टन थी। जनवरी में हुई आवक में उत्तर प्रदेश में 50 हजार टन, राजस्थान में 1.50 लाख टन, पंजाब/हरियाणा 40 हजार टन, गुजरात 15 हजार टन, मध्य प्रदेश 60 हजार टन, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं अन्य राज्यों में 50 हजार टन सरसों की आवक हुई। इस तरह फरवरी से जनवरी तक सरसों की कुल आवक 79.95 लाख टन हुई।

चालू सीजन में सरसों की कुल उपलब्धता 86 लाख टन की है, जिसमें पिछले का बकाया एक लाख टन स्टॉक शामिल है। चालू सीजन में कुल उत्पादन लगभग 85 लाख टन का होने का अनुमान है। बीते रबी सीजन में यह उत्पादन 69 लाख टन था। सरसों की बोआई सितंबर–अक्टूबर में शुरु होती है एवं नई सरसों की आवक फरवरी से शुरु हो जाती है। मार्च से इसकी आवक में तेजी आती है लेकिन जून से ऑफ सीजन शुरु हो जाने से इसकी आवक सुस्त पड़ जाती है।

देश में कुल पैदा होने वाली तिलहन में सरसों की हिस्सेदारी 25 फीसदी होती है। फसल वर्ष 2020–21 में उत्तर प्रदेश में 13.50 लाख टन, राजस्थान में 35 लाख टन, पंजाब/हरियाणा में 9.50 लाख टन, गुजरात में 4 लाख टन, मध्य प्रदेश में 8.50 लाख टन और पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत एवं अन्य राज्यों में 14.50 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान रहा।

गेहूं का निर्यात बढने का अनुमान

- वर्ष 2021–22 में गेहूं का वैश्विक उत्पादन 77.64 करोड़ टन रहने का अनुमान
- वर्ष 2020–21 में गेहूं की उपज 77.58 करोड़ टन
- वर्ष 2020–21 में भारत में गेहूं का उत्दान 10.78 करोड़ टन रहा
- भारत में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 10.36 करोड़ टन
- भारत से वर्ष 2020–21 में गेहूं निर्यात 35.97 लाख टन
- वर्ष 2021–22 में गेहूं निर्यात बढ़कर 70 लाख टन पहुंच सकता है
- भारत का गेहूं निर्यात वर्ष 2019–20 में 5.95 लाख टन था

सीरिया और इराक में उपज घटने से गेहूं के वैश्विक उत्पादन में कमी का अनुमान है। हालांकि, गेहूं की खपत में कनाडा की अच्छी मांग से बढ़त आने की बात कही गई है। गेहूं के अंतिम स्टॉक में पिछले साल की तुलना में चार फीसदी की कमी आने की संभावना है। गेहूं का निर्यात भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील और कनाडा से बढ़ेगा लेकिन यूक्रेन और अमरीका से घटने के आसार हैं। अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने वर्ष 2021–22 सीजन के लिए गेहूं के औसत भाव को 15 सेंटस बढ़ाकर 7.30 डॉलर प्रति बुशेल किया है। वर्ष 2021–22 में गेहूं का वैश्विक उत्पा दन 77.64 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह आंकलन पिछले महीने 77.86 करोड़ टन था।

वर्ष 2020–21 में गेहूं की उपज 77.58 करोड़ टन रही। वर्ष 2020–21 में भारत में गेहूं का उत्दान 10.78 करोड़ टन रहा जबकि, यह अनुमान वर्ष 2021–22 के लिए 10.95 करोड़ टन आंका गया है। भारत में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 10.36 करोड़ टन था।

भारत से वर्ष 2020–21 में गेहूं निर्यात 35.97 लाख टन रहा जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 70 लाख टन पहुंच सकता है। यह अनुमान पिछले महीने 55 लाख टन था। भारत का गेहूं निर्यात वर्ष 2019–20 में 5.95 लाख टन था। यूएसडीए ने रुस में वर्ष 2021–22 में 7.55 करोड़ टन गेहूं पैदा होने का अनुमान जताया है। कज़ाखस्तान में गेहूं का उत्पादन 1.18 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। अमरीका में 4.47 करोड़ टन, चीन में 13.69 करोड़ टन, यूरोपीयन संघ में 13.89 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2020–21 में रुस में 8.53 करोड़ टन गेहूं पैदा हुआ।

कज़ाखस्तान में 1.42 करोड़ टन, अमरीका में 4.97 करोड़ टन, चीन में 13.42 करोड़ टन, यूरोपीयन संघ में 12.69 करोड़ टन गेहूं की पैदावार हुई। वर्ष 2020–21 में गेहूं की कुल वैश्विक खपत 78.25 करोड़ टन रही जो वर्ष 2021–22 में 78.80 करोड़ टन पहुंच सकती है।

वर्ष 2020–21 में गेहूं का वैश्विक अंतिम स्टॉक 28.98 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2021–22 में 27.82 करोड़ टन रहने की संभावना है। यह वर्ष 2019–20 में 29.65 करोड़ टन रहा। भारत में गेहूं का अंतिम स्टॉक वर्ष 2020–21 में 2.78 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2021–22 में भी 2.60 करोड़ टन रहने के आसार हैं।

खाद की कमी को पूरा करने की तैयारी

वैश्विक बाजार में उर्वरक की बढती कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार ने आगामी खरीफ मौसम की जरुरतों को पूरा करने की तैयारी अभी से बढा दी है। पिछले साल के खरीफ और चालू रबी मौसम में उर्वरक वितरण को लेकर अपनाई रणनीति की कामयाबी के बाद केंद्रीय खाद्य व उर्वरक मंत्रालय ने एक समग्र कारगर नीति तैयार की है।

अगले खरीफ मौसम को लेकर घरेलू उर्वरक कंपनियों की तैयारी में अहम भूमिका है। जिसको लेकर केंद्रीय खाद्य व उर्वरक मंत्रालय ने जिला स्तर पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चत करने के लिए घरेलू कंपनियों, राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त योजना तैयार की है। दरअसल केंद्रीय खाद्य व उर्वरक मंत्रालय ने अगले खरीफ मौसम शुरु होने से पहले के महीनों में उर्वरक आपूर्ति के लिए मासिक कार्यक्रम तैयार कर लिया है। जिसके तहत देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं अप्रैल 2021 में डीएपी का ओपनिंग स्टॉक 14.5 लाख टन था।

चालू मौसम में डीएपी का स्टॉक 25 लाख टन होगा। यूरिया का ओपनिंग स्टॉक अप्रैल 2021 में 50 लाख टन था जो इस बार 60 लाख टन से अधिक होगा। वैसे तो खेती के लिए जरुरी उर्वरकों का ओपनिंग स्टॉक पिछले तीन वर्षों के औसत से अधिक है। केंद्रीय खाद्य व उर्वरक मंत्रालय ने इंटिग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) अपना रखा है जिससे उर्वरक ढुलाई की निगरानी की जा सकती है। आयातित कच्चे माल की जहाज पर लदान से लेकर बंदरगाह पर उतारने और खाद कारखाने तक पहुंचने और वहां से तैयार माल निकलने की सभी गतिविधियां इसमें शामिल है।

उर्वरक कारखानों से लेकर संबंधित जिलों तक की आपूर्ति और ताजा स्टाक तक खाद की निगरानी अब संभव है।

विदेश से बासमती चावल की खरीदारी 4 साल के निचले स्तर

भारत का बासमती चावल का निर्यात 2021 में एक साल पहले के मुकाबले 20 फीसदी घट गया है। 2021 में यह 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसकी वजह यह है कि भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदार ईरान ने अपना रुपये रिजर्व घटने के बाद खरीद घटा दी है।

सरकारी डेटा के मुताबिक, भारत का बासमती राइस एक्सपोर्ट साल 2021 में एक साल पहले के मुकाबले 20 फीसदी घटकर 40 लाख टन रह गया है। यह 2017 के बाद से सबसे कम है। भारतीय बासमती राइस के सबसे बड़े खरीद ईरान को शिपमेंट एक साल पहले से 26 फीसदी घटकर 8,34,458 टन रह गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। यह मुख्य रूप से नॉन–बासमती राइस को अफ्रीकी देशों को एक्सपोर्ट करता है। वहीं, प्रीमियम बासमती राइस का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट को किया जाता है।

सूत्रों के अनुसार, भारतीय बैंकों के साथ ईरान का रुपये का रिजर्व घटने के बाद पिछले साल कुछ महीने के लिए ईरान मार्केट में ऐक्टिव नहीं था। ईरान पहले रुपये के बदले भारत को ऑयल बेचता था। ईरान इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर कमोडिटीज समेत क्रिटिकल गुड्स इंपोर्ट करने में करता था। हालांकि, भारत ने मई 2019 में ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। ईरान ने रुपये का इस्तेमाल करते हुए भारत से सामान खरीदना जारी रखा है, लेकिन बिना क्रूड सेल्स के ईरान का रुपये का रिजर्व घटा है।

ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट का कहना है कि 2021 के मध्य में एक्सपोर्ट में सुस्ती थी, लेकिन आखिरी दो–तीन में ईरान, सउदी अरब और दूसरे प्रमुख बायर्स की तरफ से खरीदारी बढ़ी है।

On The Way Half Century 50
व्यापार एक्सप्रैस में विज्ञापन देकर लाभ उठाए
9312625326
vyaparexpress50@gmail.com
www.vyaparexpress.co

GrainEx INDIA
BRIDGING THE GAP
India's Premier Technology Oriented Exhibition & Conference on Grain Milling Industry

10th Edition Indore, Madhya Pradesh - INDIA
11th Edition Solapur, Maharashtra - INDIA
An Exposition to Expand, Explore & Ensure
Expand YOUR BUSINESS · Explore YOUR MARKET · Ensure YOUR FUTURE
An Event by adamas Events Pvt. Ltd.
ADAMAS Events Pvt. Ltd.
SCO 27, IInd Floor, Mugal Canal, KARNAL - 132001 (Haryana) India
Phone: +91-184-4036770 | +91-86074-63222
chandan@grainexindia.com | www.grainexindia.com
MEDIA PARTNER VYAPAR EXPRESS

TRIMURTI OVERSEAS LIMITED
SINCE 1980
Importer, Exporter, Indentor & Business Consultant
Basmati & Non-Basmati Rice, Pulses, Beans & Grocery Items Spices & Grains
H.O. SCO-7, Bhagya Tara Complex, Mandi Area, Gaushala Bazar, HOSHIARPUR, Punjab, India-146001 Tel. : (0) 91-1882-227103
B.O. Surrey, British Columbia, Canada
Sister Concern (India): FD Exports & Trimurti Trading Co. Pvt. Ltd.
Call: Parshotam Kumar Gupta, Director Mob. : (India) +91-98140 66219, 62830 29419 (UAE) : +971-559 587 480
Nipun Gupta Mob. : +91-87270-91919
E: staff@trmoverseas.com | www.trmoverseas.com

R.Sons GROUP
Dalal Ratilal & Sons
AN INTERNATIONALLY RENOWNED BROKERAGE GROUP
Rajkot | Indore | Surat
Head Office 13, Natraj Chamber, Bardan Gali, Danapith, Rajkot - 360 001 (Gujarat) India +91 281 2238592, +91 281 2227027
Corporate Office A-208, Market Yard, Morbi Road, Bedi, Rajkot - 360 003 (Gujarat) India. +91 281 2790108, +91 281 2790208, +91 281 2790252
Management
Sanjay Somaiya +91 98242 20036 | +91 93741 00990 | sanjayrsons208@gmail.com
Sarang Somaiya +91 99247 11220 | rsonsgroup@gmail.com
R Sons Team
Vipul Vaghela +91 94282 33978
Hitesh Patel +91 98241 40905
Jayraj Gadhvi +91 75674 55490
Dhaval Bahukiya +91 98258 94943
Kanaiya Dubey +91 99252 41122
We Deals In
Rice Grains Pulses Spices Oil Seeds Sugar Dry Fruits Wheat Products Animal Feed
Choose us and we will prove it to be your best business decision!

सतीश कुमार एंड कम्पनी
कमीशन एजेन्ट

हमारे यहाँ पर राईस प्लांट, सालवेन्ट प्लांट, घी मिल व तेल मिल, ड्रायर, सेला प्लांट, बुआयलर्ज, हर प्रकार की मशीनरी, जमीन-जायदाद, पुरानी फैक्ट्री, सोरटैक्स मशीन, आटा चक्की प्लांट, फ्लोर मिल मशीनरी कमीशन पर खरीदी व बेची जाती है। पुरानी बिल्डिंग, फैक्ट्री, कोठी आदी तुड़वाने (DEMOLISH) के लिए सम्पर्क करें।
मार्किट कमेटी रोड़, बारदाना मार्किट, करनाल (हरियाणा)
Email: satishaggarwal04462@gmail.com
सतीश कुमार अग्रवाल 92156-04462, 9215704462

RICE Basmati Specialist
DADHICH & CO.
Canvassing Agents For :-
*RICE- *WHEAT- *GRAIN
117, Mahalaxmi Market, 1st Floor, E-40, Market Yard, Gultekdi, PUNE-411037
Ph.: 020-24271907, 24017276 Fax: 24017277
Mob.: 9422321241, 9422321242

CHAWAL WALA
Ph.: 0291-2570609, 2570591
Cell.: 98291-94190 (Ravi), 98290-24609 (Rajender) 93513-21116(Mohit), 93142-08383
BHIKAM DAS MOOLCHAND PARIHAR RAMBAGASH BHIKAMDAS
7, Main Mandi, Mondore Road, JODHPUR-342007 (Raj)
Distributors For- LALQILLA-INDIA GATE-(DOON) AARTI-NURJAHAN Basmati Rice

Leading Canvassing Agent in AHMEDABAD for Rice, Wheat, Bajra, Jawar, Pulses etc.
DALAL ARUNKUMAR VISHNUPRASAD
25/2, Kabutarkhana, Kalupur, AHMEDABAD-380 002. (GUJ.)
PHONE : (O) 22169585 / 22169828 (R) 27417877
MOBILE : 9327064099 / 9824410544 Arun Vyas

भारतीय मोटे अनाज का निर्यात बढने की उम्मीद

- 2020–21 में 2.7 करोड़ डॉलर के मोटे अनाज का निर्यात
- 2019–20 में 2.85 करोड़ डॉलर के मोटे अनाज का निर्यात
- वैश्विक मोटे अनाज का निर्यात 2020 में 46.63 करोड़ डॉलर
- मोटे अनाज के प्रमुख निर्यातक अमेरिका, रुस, युक्रेन, भारत, चीन, फ्रांस, पौलेंड और अर्जेंटीना है।

केंद्र सरकार की तरफ से मोटा अनाज वर्ष 2023 की तैयारी कर रखी है। मोटे अनाज पर जारी निर्देश के तहत जारी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। इस फसलों की खेती सरकारी खरीद और उपभोक्ताओं को वितरण को लेकर नियमों में कई तरह की विसंगतियां थी जिसे तर्कसंगत बना दिया गया है। जिससे मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू स्तर पर उपभोक्ताओं के समक्ष खपत बढेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वैश्विक मोटे अनाज की बढती मांग के चलते आगामी वर्षों में भारतीय मोटे अनाज का निर्यात उल्लेखनीय रुप से बढने की उम्मीद है। दरअसल मोटे अनाज की सरकारी खरीद और इसके वितरण को लेकर 2014 में जारी दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया गया है। इसमें खरीद, आवंट, वितरण और बिक्री को नियिमि किया गया था।

इन दिशानिर्देशों में राज्यों को केंद्रीय पूल के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मोटा अनाज खरीद की अनुमति दी गई थी। जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के परामर्श से राज्य सरकार के खरीद प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरुरी थी। चूंकि मोटे अनाज की खरीद की अवधि समाप्त होने के तीन महीने के भीतर मोटे अनाज की पूरी मात्रा बांट देना जरुरी था। जिसको लेकर हाल के वर्षों में मोटे अनाज वाली फसलों की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढा है और सरकारी खरीद का दबाव भी बढा है। यद्यपि राज्य सरकारों के समक्ष मोटे अनाज के वितरण को लेकर कई तरह की कठिनाई पेश आने लगी है।

मोटे अनाज का बड़ा स्टॉक और इसके भंडारण के साथ इसके वितरण की तीन महीने की सीमित अवधि से मुश्किलें आ रही थी। इतने कम समय में इतने मोटे अनाज का वितरण करना संभव नहीं हो पा रहा था। राज्यों की तरफ से नियमों से रियायत की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से इसमें पर्याप्त संशोधन करते हुए इसकी अवधि बढा दी गई है। नए दिशानिर्देशों से राशन प्रणाली के माध्यम से मोटे अनाज की खरीद बिक्री व खपत बढाने में मदद मिलेगी। मोटे अनाज की खेती असिंचित भूमि पर होती है और इसकी खेती सीमांत किसान करते है। मोटे अनाज की मांग बढने से एक तरफ किसानों की अच्छी कीमतें मिलेंगी वहीं किसानों का रुझान मोटे अनाज की खेती की ओर होगा।

मोटे अनाज के तहत ज्वार और रागी के वितरण की अवधि को तीन महीने से बढाकर छह–सात महीने कर दिया गया है। इससे इन मोटे अनाजों की खरीद व खपत में बढोतरी होगी। राशन प्रणाली के तहत इसे बांटने में भी काफी सहूलियत होगी। मोटे अनाज की खरीद शुरु होने से पहले उपभोक्ता राज्यों को अपनी मांग को रखना होगा जिससे अंतरराज्यीय परिवहन का प्रावधान भी निर्धारित समय से किया जा सकेगा। इस समय भारत दुनिया में मोटे अनाज का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

भारत ने 2020–21 में 2.7 करोड़ डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया था। वहीं 2019–20 में मोटे अनाज का निर्यात 2.85 करोड़ डॉलर का हुआ था। मोटे अनाज के प्रमुख निर्यातक अमेरिका, रुस, युक्रेन, भारत, चीन, फ्रांस, पौलेंड और अर्जेंटीना है। जिसको वैश्विक मोटे अनाज का निर्यात 2020 में 46.63 करोड़ डॉलर था। वैश्विक स्तर पर पोषक अनाज की मांग में लगातार बढोतरी हो रही है और केंद्रीय वाणिज्य विभाग को उम्मीद है कि आगामी वर्षों में मोटे अनाज का निर्यात तेजी से बढेगा।

उर्वरक सब्सिडी में की गई करीब 25 फीसदी की कमी

वित्त वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी में करीब 25 फीसदी की कमी की गई है जिससे तीन तरह की संभावनाएं उभरती हैं। पहली संभावना यह है कि केंद्र को उम्मीद है कि अगले वर्ष अंतरराष्ट्रीय कीमतें उतनी ऊंची नहीं रहेंगी जितनी कि इस साल रहीं जिससे आगामी महीनों में भार में अपने आप कमी आ जाएगी।

दूसरी संभावना है यह है कि खुदरा कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। तीसरा तथा सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि कीमतों को कम रखने के लिए केंद्र उर्वरक सब्सिडी में धन वर्ष के मध्य में डालता है। पिछले दो वित्त वर्ष से वैश्विक दरों में इजाफा होने पर केंद्र साल के बीच में उर्वरक सब्सिडी की रकम साल के बीच में बढ़ा रहा है।

वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए करीब 79,530 करोड़ रुपये आवंटित किए थे लेकिन साल का अंत होते होते उसने उर्वरक सब्सिडी को संशोधित 1.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया। इस प्रकार इसमें 76.1 फीसदी का इजाफा किया गया था। सभी संभावनाओं पर व्यापार और बाजार के सूत्रों का कहना है कि, दूसरे और तीसरे परिदृश्य की संभावना अधिक है।

सामान्यतया किसी सामान्य वर्ष में केंद्र को यूरिया और गैर–यूरिया उर्वरकों के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की जरूरत पड़ती है। वित्त वर्ष 2023 में भले ही संशोधित अनुमान से कम लेकिन बजटीय आवंटन फिर भी काल्पनिक जरूरत से 31.5 फीसदी अधिक है। लेकिन यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या यह पूरे वर्ष की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है

सूत्रों के अनुसार, सभी उर्वरकों की मौजूदा बाजार कीमत और भविष्य के कीमत परिदृश्य को देखते हुए वित्त वर्ष 2023 में उर्वरकों के लिए बजट आवंटन अगले 6 से 7 महीनों में ही खर्च हो जाना चाहिए। उसके बाद यदि बाजार की मौजूदा परिस्थितियां बनी रहती हैं तो नए सिरे से आवंटन की आवश्यकता पड़ सकती है।

वैश्विक उर्वरक बाजार गतिशील बना हुआ है और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वित्त वर्ष 2023 में कच्चा तेल, गैस और पेट्रोलियम कीमतों में किस प्रकार का बदलाव होता है और साथ ही भूराजनीतिक तनाव क्या मोड़ लेते हैं। यदि मौजूदा बाजार कीमतें बनी रहती है तो आमराय यह है कि बजट में आवंटित 1.05 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी की रकम घरेलू खपत के मौजूदा स्तर पर 6 से 7 महीनों में समाप्त हो जानी चाहिए।

कीमत वृद्धि

आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में 28 जनवरी 2022 तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यूरिया की कीमत 357 डॉलर प्रति टन से बढ़कर करीब 869 डॉलर प्रति टन हो गई। जनवरी से कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। इससे पहले नवंबर 2021 में 959 डॉलर प्रति टन हो गया था। आयातित डाइअमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) के मामले में वैश्विक कीमतें अप्रैल 2021 के 400 डॉलर प्रति टन से बढ़कर जनवरी 2022 में 930 डॉलर प्रति टन हो गया। इस प्रकार इसमें 132.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

भारत में उर्वरकों में सबसे अधिक खपत यूरिया की होती है जिसके बाद डीएपी का स्थान है। डीएपी के मामले में सालाना खपत का लगभग आधा स्थानीय तौर पर उत्पादित किया जाता है जबकि शेष का आयात करना पड़ता है। देश में सालाना यूरिया की खपत करीब 3.3 करोड़ टन है जिसके 70 फीसदी का स्थानीय स्तर पर उत्पादन होता है और शेष का आयात किया जाता है। डीएपी को तैयार करने के लिए जरुरी अमोनिया और फॉस्फोरिक अम्ल का पूरा हिस्सा आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है।

चालू वित्त वर्ष में वैश्विक बाजारों में अमोनिया की कीमत 430 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 22 जनवरी, 2022 को 900 डॉलर प्रति टन पर था। जबकि इसी दौरान फॉस्फोरिक अम्ल की कीमत 795 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 1,330 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई।

तिलहन एवं दलहन की बुआई में हुई बढ़ोत्तरी

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, चालू रबी तिलहन के साथ ही दलहन की बुआई में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इनके आयात बिल में कटौती की संभावना है। मंत्रालय के मुताबिक, 4 फरवरी 2021 तक रबी फसलों की बुआई 1.48 फीसदी बढ़कर 700.83 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई 690.60 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

चालू रबी में तिलहन के साथ ही दलहन की बुआई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रबी की प्रमुख फसल गेहूं के साथ ही मोटे अनाजों की बुआई में कमी आई है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई चालू रबी में घटकर 343.26 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जोकि पिछले साल की समान अवधि के 346.10 लाख हेक्टेयर से कम है। तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 102.79 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई 83.69 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

रबी तिलहन की प्रमुख फसल सरसों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 91.63 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई 73.12 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। अन्य तिलहनी फसलों में सनफ्लवर की बुआई 1.19 लाख हेक्टेयर में, मूंगफली की 5.27 लाख हेक्टेयर में और सफ्लावर की 76 हजार हेक्टेयर के अलावा केस्टर सीड की बुआई 2.95 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 1.09 लाख हेक्टेयर में, 5.18 लाख हेक्टेयर में, 58 हजार हेक्टेयर और 2.80 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। दालों की बुआई चालू रबी में बढ़कर 168.27 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि इनकी बुआई 166.10 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। रबी दलहन की प्रमुख फसल चना की बुआई चालू रबी में बढ़कर 114.95 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इसकी बुआई 110.38 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी।

मसूर की बुआई चालू रबी में 17.71 लाख हजार हेक्टेयर में, मटर की 10.18 लाख हेक्टेयर में और उड़द की 8.17 हेक्टेयर में हुई है। पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इनकी बुआई क्रमशः 16.91 लाख हेक्टेयर में, 10.38 लाख हेक्टेयर में और 8.33 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मूंग की बुआई चालू रबी में 5.13 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले रबी की समान अवधि में इसकी बुआई 7.03 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी।

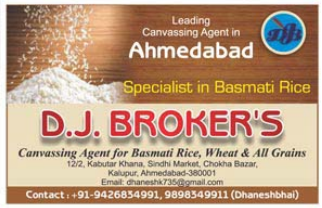

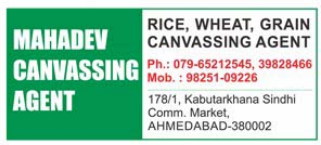

प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए एपीडा बनाएगा निर्यात मानक

केंद्रीय बजट में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर जोर को देखते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित की है। यह समिति प्राकृतिक कृषि उत्पादों के निर्यात मानक विकसित करेगी, जिसमें जीरो बजट नैचुरल फॉर्मिंग जैसे तरीकों पर विचार होगा। यह समिति फसल तैयार होने के पहले और बाद की बेहतरीन गतिविधियों, प्रामाणिक आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात संवर्धन व पौध व पशु आधारित प्राकृतिक उत्पादों पर विचार करेगी। सूत्रों के अनुसार, पौध व पशु आधारित प्राकृतिक उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण और फसल तैयार होने के बाद की तकनीकों, पैकेजिंग और लेबलिंग व बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मसलों से निपटने के लिए एक अलग उपसमूह का गठन किया गया है। अपने हाल के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रसायन मुक्त, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा

केंद्र सरकार कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में बदलाव पर भी जोर देगी, जिससे प्राकृतिक, शून्य बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्यवर्धन और प्रबंधन को बढ़ावा मिल सके। सूत्रों के अनुसार, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती से अलग है। प्राकृतिक खेती में सभी प्राकृतिक चीजों मिट्टी, पानी, वायु और पूरे इकोस्टिम पर जोर होता है, जबकि दूसरे में मिट्टी में रसायन मुक्त तत्वों के इस्तेमाल पर जोर होता है।

खाद्य तेल की कीमतों में नियंत्रण के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से इन जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। आदेश में भंडारण की सीमा का भी उल्लेख था। मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मंत्रालय ने कहा कि, बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें। लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्ति श्रृंखला और कारोबार में किसी तरह की अड़चन न आने पाए।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर लगेगी रोक

बयान में कहा गया है कि इस कदम से अनुचित व्यवहार मसलन जमाखोरी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी। राज्यों को खाद्य तेलों के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मूल्य परिदृश्य के बारे में भी बताया। राज्यों को इस बात की जानकारी दी गई कि अंतरराष्ट्रीय कीमतें किस तरह से भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही हैं।

स्टॉक लिमिट

खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है। थोक व्यापारियों के लिए यह 500 क्विंटल, थोक उपभोक्ताओं की खुदरा दुकानों मसलन बड़ी श्रृंखला और रिटेलर के लिए यह सीमा 30 क्विंटल और उनके डिपो के लिए 1,000 क्विंटल है। खाद्य तेलों के प्रसंस्करणकर्ता अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिन के बराबर का स्टॉक रख सकते हैं। वहीं तिलहनों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिए 2,000 क्विंटल है।

खाद्य तिलहनों के प्रसंस्करणकर्ता 90 दिन के खाद्य तेलों के उत्पादन के बराबर तिलहनों का स्टॉक रख पाएंगे। इस आदेश के दायरे से निर्यातकों और आयातकों को कुछ शर्तों के साथ बाहर रखा गया है।

चीनी का उत्पादन 5.65 फीसदी बढ़कर 187 लाख टन के पार

चालू पेराई सीजन 2021–22 के पहले चार महीने पहली अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक चीनी का उत्पादन 5.65 फीसदी बढ़कर 187.08 लाख टन का हो चुका है जबकि पिछले पेराई सीजन में इस दौरान केवल 177.06 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ था। चालू पेराई सीजन में 507 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई चल रही है, जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि में केवल 491 मिलों में ही पेराई चल रही थी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के मुताबिक, चालू पेराई सीजन में महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2021 तक 72.90 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 63.80 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। राज्य में 194 चीनी मिलों में पेराई आरंभ हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 182 चीनी मिलों में ही पेराई आरंभ हो पाई थी।

उत्तर प्रदेश में चालू पेराई सीजन में मिलों में देर से गन्ने की पेराई आरंभ हुई थी। हालांकि 31 जनवरी तक राज्य की सभी 120 चीनी मिलों ने पेराई आरंभ कर दी है। राज्य में 31 जनवरी 2022 तक 50.33 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है जोकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि के 54.43 लाख टन से कम है। कर्नाटक में 31 जनवरी 2022 तक 38.78 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि में केवल 34.54 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ था।

राज्य में चालू पेराई सीजन में 72 मिलों में गन्ने की पेराई चल रही है जबकि पिछले पेराई सीजन में 66 मिलों में ही पेराई चल रही थी। गुजरात में चालू पेराई सीजन में 31 जनवरी 2022 तक 15 चीनी मिलों ने पेराई आरंभ कर दी है, तथा 5.75 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि में राज्य की मिलों ने 5.55 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। तमिलनाडु में चालू पेराई सीजन में 31 जनवरी तक राज्य की मिलों ने 2.88 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवधि में राज्य में 1.65 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हुआ था।

चावल का निर्यात 19.91 लाख टन

- मूल्य के हिसाब से बासमती चावल निर्यात 17,689 करोड़ रु
- गैर बासमती चावल का निर्यात 33,350 करोड़ रुपये
- सऊदी अरब कंपनियों ने करीब 48 से 50 हजार बासमती चावल के आयात सौदे किए हैं।

दिसंबर में बासमती एवं गैर बासमती चावल का निर्यात 19.91 लाख टन का हुआ है, इसमें बासमती चावल की हिस्सेदारी 3.43 लाख टन की है, जबकि गैर बासमती चावल की हिस्सेदारी 16.48 लाख टन है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2021–22 के पहले 9 महीनों अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से बासमती चावल का निर्यात 27,45,571 टन का ही हुआ है जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात इस दौरान 125,31,425 टन का हुआ है।

मूल्य के हिसाब से बासमती चावल का निर्यात 17,689 करोड़ रुपये का हुआ है, जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात 33,350 करोड़ रुपये का हुआ है। सूत्रों के अनुसार, बासमती चावल में निर्यातकों के साथ ही स्थानीय मांग में सुधार आने से हाल ही कीमतें बढ़ी हैं। पिछले दस से पंद्रह दिनों में सऊदी अरब की कंपनियों ने करीब 48 से 50 हजार बासमती चावल के आयात सौदे किए हैं।

आगे रमजान की मांग बासमती चावल में और बढ़ने की उम्मीद है। उत्पादक मंडियों में किसानी धान की आवक कम हो गई है, जबकि स्टॉकिस्ट नीचे दाम पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए आगामी दिनों में इनकी कीमतों में हल्का सुधार और भी बन सकता है।

स्वामी, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक: टी. आर. अरोड़ा द्वारा व्यापार एक्सप्रैस के लिए 2718, गली नं. 5, बिहारी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032 से प्रकाशित तथा बालाजी आफसैट उत्पनपुर 1/11884, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 से मुद्रित। संपादक-टी. आर. अरोड़ा